बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 107

बेवजह देरी

राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट (एनसीएलटी) ने गुरुवार को ऋणदाताओं के एक समूह की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें उन्होंने जेट एयरवेज के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इससे पहले स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों का एक समूह कंपनी के लिए खरीदार तलाश कर पाने में नाकाम रहा था। गत मार्च में बैंकों के समूह द्वारा विमानन कंपनी के परिचालन का नियंत्रण करने के पहले से ही खरीदार की तलाश जारी थी। बैंकों को लग रहा था कि जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल के परिदृश्य से बाहर होने के बाद कंपनी को कोई न कोई खरीदार मिल जाएगा। परंतु बोली की औपचारिक प्रक्रिया के बाद भी केवल एक ही प्रभावी बोली सामने आई, वह भी जेट की अल्पांश हिस्सेदार और नकदी की कमी से जूझ रही अबू धाबी की एतिहाद एयरवेज की ओर से। बैंकों को इस बोली में भी तमाम समस्याएं नजर आ रही थीं, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। पहली बात, एतिहाद बहुलांश हिस्सेदार नहीं बन सकती थी। दूसरा, उसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से नियामकीय रियायत की आवश्यकता थी और आखिरी बात, बैंक एतिहाद की शर्तों पर जेट को बचाने पर जिस हद तक बैंकों के कर्ज की राशि बट्टे खाते में डालनी पड़ती, बैंक उसे लेकर भी असहज थे।

कर्जग्रस्त विमानन कंपनी की दिक्कत तब शुरू हुई जब वह गत दिसंबर में एक कर्ज चुकाने में चूक गई। अज्ञात वजहों से कर्जदाताओं ने गोयल को पर्याप्त अवसर दिया। इसे उचित ठहराना मुश्किल है। बैंकों की इस गड़बड़ी के परिणामस्वरूप जेट एयरवेज अब दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। उसकी उड़ानों का संचालन अप्रैल के मध्य से ही बंद है। महंगे लैंडिंग स्लॉट को लेकर बढ़ती चिंता, भविष्य की तिथियों के लिए बुक टिकट आदि की बात करें तो वह विमानन कंपनी की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान हैं। कंपनी पूर्व प्रबंधन और ऋणदाताओं की गलतियों की वजह से ठप हुई। यह देखना होगा कि बैंकों ने अपना कितना मूल्यह्रास किया है। क्या जेट को दिवालिया प्रक्रिया में न डालकर उन्होंने वही नुकसान तो नहीं कर लिया जिसे लेकर एतिहाद की पेशकश में वे घबरा रहे थे। फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है लेकिन इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। चाहे जो भी हो अब कंपनी एनसीएलटी के हवाले है तो कर्जदाता 8,400 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से एक छोटे हिस्से की ही वसूली की प्रत्याशा कर सकते हैं। सच का सामना करने के बजाय बैंक समूह ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने में लगा रहा कि 31 मई तक खरीदार मिल जाएगा। किसे पता बैंक कोई ठोस कदम उठाने के बजाय कितने समय तक यूं ही जेट की परिसंपत्तियां खराब होने देते? गैर वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा गत 9 जून को एनसीएलटी का रुख करने के बाद उनके हाथ बंध गए।

यह बात हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि दिवालिया प्रक्रिया में वित्तीय कर्जदाताओं की ओर से नाकामी की स्वीकारोक्ति अहम है। जब कोई परिसंपत्ति तनावग्रस्त हो जाए तो बैंकों को सुसंगत तरीके से काम करना चाहिए। वे जितनी प्रतीक्षा करेंगे उनका उतना ही नुकसान होगा। यह खेद की बात है कि बैंकिंग जगत के तमाम लोग जल्दी कदम उठाने के फायदे को समझने में नाकाम रहे। गुरुवार की सुनवाई के बाद एनसीएलटी ने निस्तारण से जुड़े पेशेवरों से कहा है कि वे इस मामले को तीन महीने के भीतर निपटाने का प्रयास करें। यह अच्छी खबर है लेकिन इससे बहुत भरोसा नहीं पैदा होता क्योंकि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के तहत निस्तारण के लिए गए मामलों में भी बहुत अधिक देरी और विवाद देखने को मिले हैं।

विनय सिन्हा

तकनीक के सहारे होगा नया शीत युद्ध

अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा द्वंद्व के मूल में तकनीकी उन्नति की होड़ भी है। इसका रक्षा-सुरक्षा क्षेत्र से सीधा संबंध है। भारत को भी इस पर ध्यान देना होगा। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **श्याम सरन**

अमेरिका और चीन एक ऐसे सामरिक विवाद में उलझे हुए हैं जो निकट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा। इस विवाद में ऐसे दौर भी आ सकते हैं जो हमने पिछली सदी में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान देखे। परंतु ये अस्थायी होंगे। दोनो देशों की प्रतिद्वंद्विता शीतयुद्ध की तरह सैन्य और वैचारिक स्तर तक नहीं जाएगी। नया शीत युद्ध तकनीक में प्रवीणता पर होगा जहां वही ताकत का प्रतीक होगी।

फिलहाल अमेरिका चीन के खिलाफ कई तरह के तकनीकी अवरोध तैयार कर रहा है और अपने साझेदारों और मित्र राष्ट्रों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह आसान नहीं है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत गहराई से शेष विश्व से जुड़ी हुई है और वह कई अहम आपूर्ति शृंखलाओं का हिस्सा भी है। उसे यूं जल्दबाजी में अलग-थलग नहीं किया जा सकता है। बीते दो दशक के दौरान चीन बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत व्यवस्थित तरीके से पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से उन्नत तकनीक हासिल करता और उसे अपनाता रहा है। सन 1978 में सुधारवादी और उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद चीन ने अपने हजारों युवाओं को विश्वस्तरीय पश्चिमी संस्थानों में अध्ययन के लिए भेजा और उनके माध्यम से अकूत ज्ञान संचय किया। इसके साथ ही चीन में वह बुनियादी सुधार आरंभ हुआ जहां वह तकनीक चाहने वाले से तकनीक तैयार करने वाला बना। इससे न केवल बीते चार दशक में उच्च स्तरीय आर्थिक वृद्धि हासिल करने में कामयाब रहा बल्कि उसने आधुनिक और तकनीक संपन्न सैन्य उपकरण बनाने में भी कामयाबी हासिल की। अमेरिका के कदम चीन के शक्ति संचय में कमी ला सकते हैं, लेकिन जब तक घरेलू राजनीतिक विसंगति का हस्तक्षेप नहीं होता, लगता नहीं कि हालात उलटेंगे। इसकी आशंका बहुत कम है क्योंकि तकनीकी क्षमताएं अब व्यापक निगरानी तक पहुंच गई हैं और घरेलू सुरक्षा चुनौतियों को भी तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सकती है।

तकनीकी पहुंच पर रोक की प्रतिक्रिया स्वरूप चीन अपने घरेलू नवाचार और विकास पर दोगुना जोर दे रहा है। वह कई मूलभूत प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है जो चीन 2025 योजना का हिस्सा हैं। इसमें आईटी, मशीन शिक्षण, क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम मेधा जैसी चीजें शामिल हैं। फिलहाल चीन सेमी कंडक्टर के मामले में पीछे है और वर्ष 2018 में उसने करीब 30,000 करोड़ डॉलर मूल्य के सेमी कंडक्टर का आयात किया।

अब इस क्षेत्र में भारी निवेश की घोषणा की गई है। अगले कुछ वर्ष में इस क्षेत्र में 10,000 से 15,000 करोड़ डॉलर का निजी और सार्वजनिक निवेश किया जाएगा। बायडू, अलीबाबा और हुआवे जैसी चीन की बड़ी कंपनियां अपनी माइक्रोचिप बनाने पर काम कर रही हैं। अलीबाबा ने गत वर्ष सितंबर में अपना सेमी कंडक्टर विभाग पिंगटोग शुरू किया ताकि कृत्रिम मेधा वाली चिप बनाई जा सकें। इनका इस्तेमाल क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट से जुड़े उपकरणों में करना है। हुआवे अगले पांच वर्ष तक हर वर्ष 30,000 करोड़ डॉलर का निवेश नई पीढ़ी की चिप डिजाइन करने और बनाने में खर्च करेगा। गत वर्ष अगस्त में उसने 7 एनएम की चिप जारी की थी। क्वांटम कंप्यूटिंग में चीन अमेरिका से आगे है और वर्ष 2017 तक उसने अमेरिकी कंपनियों की तुलना में दोगुने पेटेंट फाइल किए थे।

बिना निजता की चिंता किए नागरिकों के आंकड़ों के भारी भरकम डेटा का लाभ लेते हुए चीन ने कृत्रिम मेधा क्षेत्र में क्षमताओं का विकास करने को प्राथमिकता पर रखा है। उसकी नई पीढ़ी की कृत्रिम मेधा विकास योजना देश को सन 2030 तक कृत्रिम मेधा और उससे संबंधित तकनीक के मामले में दुनिया का नेतृत्वकर्ता बनाना चाहती है। सन 2015 में चीन ने शोध और विकास पर 37,600 करोड़ डॉलर की राशि व्यय की। सन 1991 में यह राशि 130 करोड़ डॉलर थी। अब वह शोध एवं विकास व्यय के मामले में जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के मिलेजुले व्यय को पार कर गया है।

चीन की सैन्य नीति के केंद्र में भी तकनीक ही है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि बीते दो दशक में चीन ने असैन्य और सैन्य सम्मिश्रण पर काम किया है। वह बहुत सचेत ढंग से असैन्य क्षेत्र की तकनीक को सैन्य प्रयोग में लाता है। इनमें वे तकनीक भी शामिल हैं जो वह विदेश से वाणिज्यिक वजहों से हासिल करता है। वह अपनी साइबर क्षमताओं की सहायता से अमेरिकी फर्मों की वर्षों के शोध से हासिल सैन्य तकनीक को हासिल कर लेता है। चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक और संवेदनशील जगहों पर काम कर रहे चीनी विद्वानों से अक्सर गोपनीय जानकारी और योजनाएं चीनी संस्थान हासिल करते रहे हैं। परंतु चीन अपने शोध के जरिये भी तमाम तकनीकी बढ़त हासिल कर रहा है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। उसकी तकनीकी क्षमताओं में सुधार के साथ उसकी सैन्य नीति में भी बदलाव आया। पहले चरण में चीन ने सन 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से सबक लिए। इसमें अमेरिकी सेना ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल और इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया और इराक की पारंपरिक सेना को पीछे छोड़ दिया। इससे सूचना आधारित युद्ध की शुरुआत हुई जिसने चीनी सैन्य नियोजकों को प्रभावित किया और उन्होंने इसमें सिद्धहस्त होने का प्रयास आरंभ किया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का पुनर्गठन करके उसे जमीन, समुद्र और हवा में मार करने लायक बनाने के अलावा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंग के लिए तैयार करना इसका हिस्सा है। सन 1996 में चीन को ताइवान की खाड़ी में दो अमेरिकी कैरियर ग्रुप के समक्ष शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसने तैयारी शुरू की कि भविष्य में अमेरिका के ऐसे किसी भी कदम से निपट सके। तब 1000 किमी तक मार करने वाली डीएफ-21 ऐंटी कैरियर बैलिस्टिक मिसाइल सामने आई। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में जो कृत्रिम द्वीप बनाए और उनका सैन्यीकरण किए, उसमें कहीं न कहीं उसके मन में यह भावना थी कि उसके पास अमेरिका का प्रतिरोध करने की क्षमता है। हाल के दिनों में चीन के सैन्य रणनीतिकार कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस आधारित युद्ध की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर पहले मामला सूचनात्मक प्रणाली का था तो अब बात अलगोरिद्म आधारित प्रतिस्पर्धा की है जिसमें चीन को लगता है कि वह अमेरिका से आगे है।

अमेरिका में फिलहाल एक प्रभावी और विश्वसनीय प्रतिकार नीति की बात चल रही है लेकिन इन बातों का संबंध भारत की सुरक्षा से भी है। हमें इनका व्यापक और सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा ताकि आगामी चुनौतियों से निपटा जा सके। शुरुआती दौर के चीन की तरह हमें अल्पावधि में ऐसी क्षमताएं विकसित करनी होंगी जो चीन की आक्रामकता का मुकाबला कर सकें। समय के साथ हमें उभरती तकनीकी क्षमता विकसित करनी होगी जो भूराजनैतिक प्रभाव का आधार है।

इंदिरा गांधी से कैसे अलग होगा निर्मला सीतारमण का बजट?

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

लगभग आधी शताब्दी पहले भारतीय संसद में पहली बार किसी महिला ने आम बजट पेश किया था। वह इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने 28 फरवरी, 1970 को 1970-71 का बजट पेश किया था। वह उस समय प्रधानमंत्री थीं और उनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था।

भारी जनादेश के बाद सत्ता में लौटी मोदी सरकार का पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभवत: इस अतीत से वाकिफ होंगी। वह यह जानने के लिए भी उत्सुक होंगी कि आधी शताब्दी पहले इंदिरा ने देश की आर्थिक चुनौतियों का समाधान कैसे किया था। हालांकि जिन परिस्थितियों में इंदिरा ने फरवरी 1970 में अपना एकमात्र बजट पेश किया था और जिन परिस्थितियों में सीतारमण 5 जुलाई को अपना पहला बजट पेश करेंगी, वे पूरी तरह अलग हैं।

इंदिरा ने अर्थव्यवस्था में तूफान लाने वाले नीतिगत उपायों के कुछ महीने बाद बजट पेश किया था। इन उपायों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बड़े औद्योगिक घरानों के एकाधिकार तथा विस्तार को रोकने के लिए बनाया गया कानून शामिल था। यह आम चुनावों से पहले उनका अंतिम बजट था जो मार्च 1971 में होने थे। सीतारमण के साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। उनका बजट नई सरकार की आर्थिक नीतियों की शुरुआत होगी। उनके बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर कोई बड़ा उपाय नहीं किया गया है। नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर से अर्थव्यवस्था में व्यापक हलचल हुई लेकिन उन्हें दो से तीन साल हो चुके हैं।

साथ ही वे परिस्थितियां भी एकदम अलग हैं जिनमें इंदिरा और सीतारमण वित्त मंत्री बनीं। मोरारजी देसाई के जुलाई 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ऐन पहले वित्त मंत्री का पद छोड़ दिया था जिसे इंदिरा को संभालना पड़ा था। दूसरी ओर सीतारमण ने अरुण जेटली का स्थान लिया। जेटली ने खराब स्वास्थ्य के कारण यह जिम्मेदारी लेने में असमर्थता जताई थी। फिर भी सीतारमण को अपने पहले बजट में जिन समस्याओं का हल निकालना होगा वे उन समस्याओं से बहुत अलग नहीं हैं जिनका सामना इंदिरा को 1970 में अपने बजट को अंतिम रूप देते हुए करना पड़ा था। इंदिरा के बजट भाषण के अंतिम पैरे को देखिए। उन्होंने कहा, 'श्रीमान भाषण खत्म करने से पहले मैं कहना चाहती हूं कि इस सम्मानित सदन में अपना पहला बजट पेश करते हुए मैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की मौजूदा चुनौतियों और बाधाओं से अच्छी तरह वाकिफ हो गई हूं। हमारे पास विकास के कई अवसर हैं और इस उद्देश्य के लिए संसाधनों को बढ़ाने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। अगर विकास की जरूरत तात्कालिक है तो सामाजिक कल्याण के लिए कुछ उपाय करने भी जरूरी हैं। संसाधनों की किसी तत्काल आवश्यकता के बावजूद राजकोषीय प्रणाली को आय, खपत और धन में व्यापक समानता के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करना है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के जिन क्षेत्रों में निजी पहल और निवेश की जरूरत है उन्हें भी अर्थव्यवस्था के व्यापक हित को देखते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं केवल उम्मीद कर सकती हूं कि जो प्रस्ताव मैंने अभी पेश किए हैं वे बहुत कम या बहुत अधिक प्रयास करने के विपरीत खतरों से दूर हैं।'

जब इंदिरा ने बजट पेश किया तो अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय, संसाधनों को बढ़ाना, सामाजिक कल्याण और निजी निवेश को बहाल करना उनकी प्राथमिकता थी। 2019-20 के बजट को अंतिम रूप देने में लगीं सीतारमण के दिमाग में भी ये बातें चल रही होंगी। लेकिन आज अर्थव्यवस्था की स्थिति 50 साल पहले की तुलना में बहुत जटिल है और वित्त मंत्री के नीतिगत विकल्प इंदिरा की तुलना में ज्यादा सीमित हैं। वह इन मुश्किल लक्ष्यों को कैसे हासिल करेंगी, इस सवाल का जवाब 5 जुलाई को मिल जाएगा।

उदाहरण के लिए कराधान के सवाल पर इंदिरा ने कर आधार बढ़ाने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा, 'कर आधार बढ़ाने में हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि पहले से लगाए गए करों की चोरी न हो। मैंने कर प्रणाली की कुछ खामियों को दूर करने का प्रयास किया है और कुछ ऐसी रियायतों को खत्म कर दिया है जिनकी उपयोगिता खत्म हो गई है।' कर आधार बढ़ाना और कर प्रणाली की खामियों को दूर करना अधिकांश वित्त मंत्रियों की प्राथमिकता रही है और सीतारमण के भी इसी राह पर चलने की उम्मीद है।

लेकिन कर दरों के सवाल पर वह शायद ही इंदिरा का अनुसरण करेंगी। इंदिरा ने दो लाख रुपये से अधिक की आय पर अधिकतम कर दर बढ़ाकर 93.5 फीसदी की थी जिसमें दस फीसदी अधिभार भी शामिल था। 1973-74 में अधिकतम दर और बढ़कर 97.5 फीसदी पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद चीजें बदलनी शुरू हुईं। करीब 20 साल पहले भारत में व्यक्तिगत कर के लिए मध्यम कर दर प्रणाली की शुरुआत हुई और कर की तीन श्रेणियां 10 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी बनाई गई। वर्ष 2017-18 से 10 फीसदी की श्रेणी को बढ़ाकर पांच फीसदी कर दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कंपनियों के लिए भी कर की दरों में कमी की है। सालाना 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए यह 25 फीसदी और उससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए 30 फीसदी रखी गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि सभी कंपनियों को 25 फीसदी के दायरे में लाया जाएगा। इसलिए सीतारमण की चुनौती पूरी तरह अलग और ज्यादा कारगर व्यवस्था बनाना है। उनके लिए यह आसान नहीं होगा। अधिकांश वित्त मंत्री बजट भाषण के समय माहौल को हल्का फुल्का बनाने की कोशिश करते हैं। इंदिरा ने एक कर प्रस्ताव में संशोधन के बारे में कहा, 'जो स्वर्ग में एक साथ रहते हैं, उन्हें एक कर संग्रहकर्ता को अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए आय और धन के कराधान के प्रयोजन के लिए पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों की आय और धन को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए।' क्या सीतारमण से अपने बजट भाषण के दौरान इस तरह के हास्यबोध की उम्मीद की जा सकती है?

कानाफूसी

वातानुकूलित गौशाला

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश में प्रस्तावित स्मार्ट गौशालाओं के लिए कॉर्पोरेट मॉडल बनाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में राज्य सरकार एक कंपनी से बातचीत कर रही है जो प्रदेश की छह लाख से अधिक गायों के लिए स्मार्ट गौशालाओं का निर्माण करेगी। अगले पांच वर्ष तक हर वर्ष 60 गौशालाओं का निर्माण करके इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इस स्मार्ट गौशाला प्रोजेक्ट के लिए धन की व्यवस्था मनरेगा और सीएसआर फंड के माध्यम से की जाएगी। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में भी गौशाला का मुद्दा अहम था और कांग्रेस ने वादा किया था कि वह प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनवाएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि गौ संरक्षण का दम भरने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार ने 15 साल के कार्यकाल में यहां एक भी गौशाला नहीं बनवाई।

सुनवाई नहीं

केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन बार-बार यह अपील कर चुके हैं कि हर सरकारी फाइल से एक जीवन जुड़ा हुआ है। वह कहते रहे हैं कि इन फाइलों से मानवीय तरीके से निपटा जाना चाहिए। परंतु ऐसा लगता नहीं कि सरकारी कार्यालयों में कोई बदलाव आया है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल के राज्य सचिवालय में एक लाख से अधिक फाइलें लंबित हैं। इनमें से 25 हजार से अधिक फाइलें तो कम से कम तीन वर्ष से लंबित हैं। यह रिपोर्ट उस समय सामने आई है जब एक अनिवासी भारतीय कारोबारी ने आत्महत्या कर ली है। कारोबारी ने कथित रूप से तब आत्महत्या कर ली जब स्थानीय निकायों ने तमाम वजहें गिनाते हुए उसके कुछ निर्माण कार्य की मंजूरी रोक दी थी।

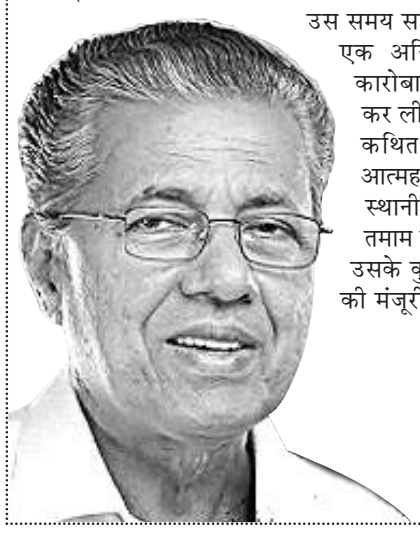

आपका पक्ष

योग से स्वस्थ होगा पूरा देश

भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2015 में योग को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी महासभा में स्वीकृति दी। तब से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्लाइमेट एक्शन रखी गई है। योग विशेषज्ञों के मुताबिक प्रतिदिन योग करने से मन और मस्तिष्क स्थिर रहता है और योग करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा यह कई बीमारियों को नियंत्रित करने में और कई बीमारियों से मनुष्य को दूर रखता है। लोगों को योग करने से सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। इसलिए योग को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने अपनाया है। आज लोग कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। रक्तचाप और मधुमेह के मरीज लगभग हर घर में हैं। आज भारत में आठ में से एक व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की शिकायत है। व्यस्त जीवन शैली की वजह से पुरुष और महिलाएं अवसादग्रस्त रहते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा अवसादग्रस्त होती हैं। इसलिए खुद को बीमारियों से दूर रखने के लिए और खुद को तनावमुक्त रखने के लिए लोग अपनी जीवन शैली में योग अपना रहे हैं। चिकित्सक भी योग करने की सलाह देते हैं। देश में विद्यार्थियों को योग शिक्षा देनी चाहिए या नहीं, यह चर्चा का विषय है। देश के अधिकतर बच्चे मैदान में खेलने के बजाय मोबाइल में खेलने लगे हैं। इससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए योग को स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

इस साल विश्व योग दिवस की थीम क्लाइमेट एक्शन रखी गई है *फोटो-पीटीआई*

बिहार में लू से जागरूकता ही बचाव

बिहार में लू से मौत की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार लू से मरने वालों की संख्या करीब 90 हो गई है। विभाग के आंकड़े के अनुसार लू के कारण सबसे अधिक मौत औरंगाबाद जिले में हुई है। औरंगाबाद जिले में लू से अबतक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। गया जिले में 35 तथा नवादा जिले में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने गया जिले में धारा 144 भी लागू की है जिससे व्यक्ति घर से नहीं निकले तथा लू से बच सके। बिहार के कई जिले अब भी गर्मी की भीषण चपेट में है जबकि देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। राज्य सरकार को भी गर्मी बढ़ने पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक कर लू की चपेट में आने से बचाया जा सकता है। सरकार को जगह-जगह पीने के पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सरकार को पीने के पानी के अलावा शर्बत आदि का भी वितरण करना चाहिए। इससे लोग पानी पीने के लिए प्रेरित होंगे जिससे शरीर में पानी की कमी के कारण लू लगने का खतरा कम होगा। इसके लिए सरकार स्वयं सेवी संगठनों की मदद भी ले सकती है। गर्मी के दिनों में स्वयं सेवी संगठन जगह-जगह पर शर्बत बांटते भी हैं लेकिन यह नाकाफी होता है। अगर सरकार ऐसी योजना पर काम करे तो कई लोगों को असमय मृत्यु से बचाया जा सकता है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।